SCAT NEWS
स्कैट समाचार

The Latest Update on Whats Happening
Around Us In The World Of Satellite & Cable TV

सैटेलाइट और केबल टीवी की दुनिया में
हमारे चारों तरफ क्या हो रहा उसका नवीनतम अपडेट

GOVT GETS SWEEPING POWERS OVER TV RATINGS

The Ministry of Information & Broadcasting (MIB) has introduced sweeping national security provisions under the TV Ratings Policy 2026, empowering the government to suspend, restrict, or even take over rating agencies without prior notice. The rules allow intervention in emergencies, war-like situations, or national security concerns, including control over infrastructure and operations. Agencies failing to comply risk cancellation of registration and a five-year ban, with no compensation for disruptions. The policy also restricts operations in sensitive geographies and prohibits cross-border data transfer, reinforcing data sovereignty in India's audience measurement ecosystem.

OTT, DPOS TO PUBLISH VIEWERSHIP DATA

In a major shift, the MIB has allowed DPOs, OTT platforms, and Big Tech firms to publish their own viewership data without requiring registration as rating agencies. The provision creates a parallel data ecosystem alongside traditional panel-based ratings, enabling platforms to leverage census-level user data. The move is expected to reshape media planning and advertising, with platform analytics offering more granular and real-time insights.

TDSAT NOTICE TO PRASAR BHARATI

TDSAT has issued a notice to Prasar Bharati following a petition by AIDCF challenging the onboarding of linear TV channels on the WAVES OTT platform. The case raises questions around regulatory parity, with AIDCF arguing that OTT platforms are not recognised distribution entities under existing guidelines. The matter will be heard next on April 29, with industry closely watching its implications for broadcast-digital convergence.

टीवी रेटिंग पर सरकार को मिले व्यापक अधिकार

सूचना और प्रसारण मंत्रालय (आईएंडबी) ने टीवी रेटिंग नीति 2026 के तहत राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित व्यापक प्रावधान लागू किये हैं, जो सरकार को बिना पूर्व सूचना के रेटिंग एजेंसियों को निलंबित करने, प्रतिबंधित करने या यहां तक कि अपने नियंत्रण में लेने का अधिकार देते हैं। ये नियम आपात स्थितियों, युद्ध जैसी परिस्थितियों या राष्ट्रीय सुरक्षा संबंधी चिंताओं के मामलों में हस्तक्षेप की अनुमति देते हैं, जिसमें बुनियादी ढांचे और संचालन पर नियंत्रण शामिल है। अनुपालन न करने वाली एजेंसियों का पंजीकरण रद्द किया जा सकता है और उन पर पांच साल का प्रतिबंध लगाया जा सकता है, साथ ही व्यवधानों के लिए कोई भी मुआवजा नहीं दिया जायेगा। यह नीति संवेदनशील भौगोलिक क्षेत्रों में संचालन को प्रतिबंधित करती है और सीमा पार डेटा हस्तांतरण पर रोक लगाती है, जिससे भारत के दर्शक मापन तंत्र में डेटा संप्रभुत्ता को मजबूती मिलती है।

ओटीटी, डीपीओ अब डेटा व्यूअरशिप पब्लिश कर सकेंगे

एक बड़े बदलाव के तहत, एमआईबी ने डीपीओ, ओटीटी प्लेटफॉर्म और बड़ी टेक कंपनियों को रेटिंग एजेंसी के तौर पर पंजीकृत हुए बिना ही अपना व्यूअरशिप डेटा पब्लिश करने की अनुमति दे दी है। इस प्रावधान से पारंपरिक पैनल आधारित रेटिंग के साथ-साथ एक समानांतर डेटा इकोसिस्टम तैयार होगा, जिससे प्लेटफॉर्म जनगणनास्तर के यूजर डेटा का लाभ उठा सकेंगे। उम्मीद है कि इस कदम से मीडिया प्लानिंग और विज्ञापन का स्वरूप बदल जायेगा, क्योंकि प्लेटफॉर्म एनालिटिक्स से ज्यादा बारीक और रीयल टाइम जानकारी मिल सकेगी।

टीडीसेट का प्रसार भारती को नोटिस

एआईडीसीएफकी एक याचिका के बाद टीडीसेट ने प्रसार भारती को नोटिस जारी किया है। इस याचिका में वेव्स ओटीटी प्लेटफॉर्म पर लीनियर चैनलों को शामिल किये जाने को चुनौती दी गयी। यह मामला रेगुलेटरी समानता को लेकर सवाल खड़े करता है, यचिकाकर्ता का तर्क है कि मौजूदा दिशानिर्देशों के तहत ओटीटी प्लेटफॉर्म को मान्यता प्राप्त वितरण संस्थाओं के रूप में नहीं माना जाता है। 29 अप्रैल को मामले की अगली सुनवाई पर उद्योग इस बात पर बरीकी से नजर रखे हुआ है कि प्रसारक और डिजिटल के मेल से इसका क्या असर पड़ेगा।

TARIFF REGIME SKEWS REVENUE TOWARDS DISTRIBUTOR

India's broadcasting market is facing structural distortions under the current TRAI tariff framework, with nearly 80% of revenues shifting towards distribution players, according to an Esya Centre study. The report highlights the dominance of DPOs in pricing, packaging, and consumer access, creating an imbalance despite broadcasters bearing content investment risks. The two-part pricing model under NTO continues to impact pay-TV growth and consumer welfare.

टैरिफ व्यवस्था से वितरक की ओर झुक रहा है राजस्व

Esya सेंटर की स्डटी के अनुसार, भारत का प्रसारण बाजार मौजूदा ट्राई टैरिफ फ्रेमवर्क के तहत ढ़ांचागत विकृतियों का सामना कर रहा है, जिसमें लगभग 80% राजस्व वितरण कंपनियों की ओर जा रहा है। रिपोर्ट में मूल्य, पैकेजिंग और कंज्यूमर एक्सेस में डीपीओ के दबदबे को उजागर किया गया है, जिससे प्रसारक द्वारा कंटेंट निवेश का जोखिम उठाने के बावजूद असंतुलन पैदा हो रहा है। एनटीओ के तहत दो भाग वाला प्राइसिंग मॉडल पे-टीवी विकास और उपभोक्ता कल्याण पर असर डालता रहेगा।

MIB CANCELS 114 MSO LICENCES

The MIB has cancelled 114 MSO registrations due to non-compliance and security clearance issues, taking the total number of operators exiting the sector to 1,159. The number of active MSOs has declined to 756, reflecting ongoing consolidation and stricter regulatory enforcement in the cable distribution ecosystem.

सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय
MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING
सत्यमेव जयते

एमआईबी ने 114 लाइसेंस रद्द किये

एमआईबी ने नियमों का पालन न करने और सुरक्षा मंजूरी से जुड़ी समस्याओं के कारण 114 एमएसओ के पंजीकरण रद्द कर दिये हैं, जिससे इस क्षेत्र को छोड़ने वाले ऑपरेटरों की कुल संख्या 1159 हो गयी है। सक्रिय एमएसओ की संख्या घटकर 756 रह गयी है, जो केबल वितरण व्यवस्था में चल रहे एकीकरण और सख्त नियामक प्रवर्तन को दर्शाता है।

NDTV DELAYS GOODTIMES ACQUISITION

NDTV has extended the timeline for completing its acquisition of the GoodTimes channel by an additional three months, citing pending regulatory approvals. The deal, valued at around Rs 18 crore, is being executed through a business transfer agreement involving cash and ad inventory.

एनडीटीवी ने गुडटाइम्स के अधिग्रहण में देरी की

एनडीटीवी ने गुडटाइम्स चैनल के अधिग्रहण को पूरा करने की समयसीमा को तीन महीने और बढ़ा दिया है। इसके पीछे कंपनी ने रेगुलेटरी मंजूरियों के लंबित होने का हवाला दिया है। यह सौदा, जिसकी कीमत लगभग 18 करोड़ रुपये है, एक बिजनेस ट्रांसफर अनुबंध के जरिए पूरी की जा रही है। इसमें कैश और एड इन्वेंट्री शामिल है।

BROADCASTERS FLAG RISING DTH SMUGGLING

Broadcasters have raised concerns over organised smuggling of Indian DTH set-top boxes into neighbouring countries, urging TRAI and MIB to tighten regulations. Industry stakeholders have called for geo-blocking mechanisms and diplomatic intervention via the Ministry of External Affairs. The issue is seen as a growing piracy threat, with illegal cross-border signal distribution impacting revenues.■

प्रसारकों ने डीटीएच की तस्करी पर चिंता जताई

प्रसारकों ने पड़ोसी देशों में भारतीय डीटीएच सेट टॉप बॉक्स की संगठित तस्करी पर चिंता जतायी है और ट्राई व एमआईबी से नियमों को और सख्त करने की अपील की है। उद्योग से जुड़े लोगों ने जियो-ब्लॉकिंग सिस्टम और विदेश मंत्रालय के जरिए कूटनीतिक दखल की मांग की है। इस मामले को पायरेसी के बढ़ते खतरे के तौर पर देखा जा रहा है, क्योंकि सीमा पार से होने वाले अवैध सिग्नल वितरण से कमायी पर बुरा असर पड़ रहा है।■